भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *109

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

पेमेंट गेटवे में तकनीकी खराबी

*109. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय बैंक चैनलों और सिडबी (एसआईडीबीआई) को जोड़ने वाली पेमेंट गेटवे प्रणालियों में तकनीकी खराबी के कारण महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में किसान लगभग डेढ़ वर्ष से विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत राजसहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के विलंब के कारण किसानों को अपने ऋणों पर अतिरिक्त ब्याज और जुर्माने का भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ा है;

(ग) क्या सरकार ने इन तकनीकी खराबियों को दूर करने और राजसहायता राशि का सुचारू और समय पर अंतरण सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन कठिनाईयों के समाधान के लिए संभावित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में प्रभावित किसानों को सभी लंबित राजसहायता तत्काल संवितरित करने के लिए कोई अंतरिम प्रावधान किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे विलंब के कारण किसानों पर लगाए गए ब्याज और जुर्माने को माफ करने, वापस लौटाने या उसकी प्रतिपूर्ति करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“भुगतान गेटवे में तकनीकी गड़बड़ियों” के संबंध में 08 दिसंबर, 2025 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *109 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) महाराष्ट्र और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, सहकारी बैंकों, राष्ट्रीय बैंक चैनलों और सिडबी को जोड़ने वाली भुगतान गेटवे प्रणालियों में ऐसी किसी तकनीकी गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली थी, जिससे महाराष्ट्र राज्य में केंद्र सरकार की योजनाएं प्रभावित हुई हों।

*****